



महानगरपालिका चुनाव: 15 जनवरी और महाराष्ट्र के शहरों की कसौटी

संपादकीय... |

जनवरी 2026 के मध्य में होने वाले महानगरपालिका चुनावों से पहले महाराष्ट्र एक बार फिर अपने शहरी भविष्य को लेकर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 15 जनवरी 2026 को होने वाली यह वोटिंग केवल नगर निगमों के गठन का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि राज्य के बड़े शहर नागरिक हितों से संचालित होंगे या सत्ता की राजनीति से। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के शोर में अक्सर दब जाने वाले महानगरपालिका चुनाव दरअसल आम नागरिक के जीवन को सबसे सीधे प्रभावित करते हैं।

दिसंबर 2025 में नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब राज्य की निगाहें मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक और छत्रपति संभाजीनगर जैसी महानगरपालिकाओं पर टिकी हैं। ये शहर केवल जनसंख्या या भूगोल के कारण महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहीं से राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और शहरी नीति की दिशा तय होती है। इन नगर निगमों पर नियंत्रण का अर्थ है हजारों करोड़ के बजट और लाखों नागरिकों की दैनिक जरूरतों पर निर्णय का अधिकार।

चिंता की बात यह है कि महानगरपालिका चुनाव भी लगातार स्थानीय मुद्दों से भटकते हुए सत्ता संघर्ष का रूप लेते जा रहे हैं। पानी की अनियमित आपूर्ति, कचरा प्रबंधन की बदहाली, जाम होती सड़कें, बढ़ता प्रदूषण, झोपड़पट्टियों की उपेक्षा और अवैध निर्माण—ये सभी समस्याएँ हर शहर में मौजूद हैं। इसके बावजूद चुनावी विमर्श में इनकी जगह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और दलों की आपसी लड़ाई ले लेती है। परिणामस्वरूप नागरिक मुद्दे पीछे और सत्ता समीकरण आगे हो जाते हैं।

महानगरपालिकाओं की सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि वे राजनीतिक नियंत्रण में तो रहीं, लेकिन वास्तविक अर्थों में स्वायत्त शहरी संस्थाएँ नहीं बन पाईं। लंबे समय तक चुनाव न होने, प्रशासकों के भरोसे शहर चलने और निर्णयों के केंद्रीकरण ने शहरी लोकतंत्र को कमजोर किया है। जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, तो जवाबदेही भी कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि आम नागरिक को नगर निगम अपने नहीं, बल्कि दूर बैठे सत्ता केंद्रों का विस्तार प्रतीत होते हैं।

भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता भी इस चुनाव का अहम संदर्भ है। ठेकेदारी व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और कचरा निपटान जैसे मुद्दे केवल तकनीकी नहीं हैं, बल्कि अक्सर राजनीतिक संरक्षण से जुड़े रहे हैं। जब तक नगर निगमों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया स्थापित नहीं होती, तब तक शहरी विकास योजनाओं की सफलता संदिग्ध बनी रहेगी।

स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम नागरिक ने इनका वास्तविक लाभ महसूस किया है? तकनीक तभी सार्थक है जब वह झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिक से लेकर कर देने वाले मध्यमवर्ग तक, सभी के जीवन को बेहतर बनाए। महानगरपालिका चुनावों में मतदाताओं को इन्हीं कसौटियों पर उम्मीदवारों और दलों को परखना होगा।

इन चुनावों में मतदाता की भूमिका सबसे निर्णायक है। दुर्भाग्य से महानगरपालिका चुनावों में मतदान प्रतिशत हमेशा अपेक्षाकृत कम रहा है। नागरिक अक्सर यह मान लेते हैं कि इन चुनावों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। पानी, सफाई, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल और प्राथमिक शिक्षा—इन सभी का सीधा संबंध नगर निगमों से है। यदि मतदाता सजग नहीं हुआ, तो अयोग्य नेतृत्व चुना जाएगा और फिर शिकायत की गुंजाइश भी सीमित रह जाएगी।

राजनीतिक दलों के लिए भी यह चुनाव आत्ममंथन का अवसर है। क्या वे शहरों के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टि लेकर मैदान में उतर रहे हैं या केवल सत्ता विस्तार के उद्देश्य से? क्या उम्मीदवारों का चयन योग्यता, ईमानदारी और प्रशासनिक समझ के आधार पर हो रहा है, या फिर केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर? यदि महानगरपालिका चुनाव भी पुरानी राजनीति का दोहराव साबित हुए, तो शहरी संकट और गहराएगा।

संपादकीय दृष्टि से, 15 जनवरी 2026 को होने वाले महानगरपालिका चुनाव महाराष्ट्र के शहरी भविष्य की वास्तविक कसौटी हैं। यह तय होगा कि शहर नागरिकों के लिए हैं या सत्ता के लिए। यदि मतदाता ने सही सवाल पूछे, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी और विकल्पों को गंभीरता से परखा, तभी महानगरपालिकाएँ सच्चे अर्थों में स्वशासन की संस्थाएँ बन सकेंगी। अन्यथा यह अवसर भी इतिहास में एक और चूका हुआ मौका बनकर दर्ज हो जाएगा।

बांग्लादेश | बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं;

बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं, यूनुस सरकार ने खारिज की भारत की चिंता, बताया- गुमराह करने वाला

ढाका | बांग्लादेश ने रविवार को अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत की चिंता को खारिज कर दिया है। उसने भारत के बयानों को "गलत, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और गुमराह करने वाला" बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारत का बयान सही तथ्यों को नहीं दर्शाती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऐसे बयान बांग्लादेश की सांप्रदायिक सद्भाव की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को गलत तरीके से पेश करती हैं। बांग्लादेश ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को आपराधिक घटनाएं बताया और कहा कि भारत इसे व्यवस्थित उत्पीड़न के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है।

बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा प्रेस को जारी बयान में बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने लिखा, "हम देखते हैं कि आपराधिक कृत्यों की अलग-थलग घटनाओं को हिंदुओं के व्यवस्थित उत्पीड़न के रूप में पेश करने के व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं



और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेश विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कुछ हलकों में एक चयनात्मक और अनुचित पूर्वाग्रह देखते हैं, जहां अलग-थलग घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, गलत तरीके से पेश किया जाता है और आम भारतीयों को बांग्लादेश, उसके राजनयिक मिशनों और भारत में अन्य प्रतिष्ठानों के

खिलाफ भड़काने के लिए प्रचारित किया जाता है।"

बांग्लादेश ने अमृत मंडल की हत्या का किया जिक्र अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट-पीटकर हत्या की घटना का जिक्र करते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा, "इसे अल्पसंख्यक उत्पीड़न के उदाहरण के रूप में पेश करना "गुमराह करने वाला" था।"

WORLD NEWS | 36 घंटे में 80 ड्रोन अटैक...

36 घंटे में 80 ड्रोन अटैक... पाकिस्तान ने कबूला सच, माना- भारत के हमले में नूर खान एयरबेस हुआ बर्बाद

● NEWS AGENCY

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की है कि भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में नूर खान एयर बेस पर हमला किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ और वहां तैनात सुरक्षाकर्मी घायल हुए। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई के शुरुआती हफ्ते में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की हिमाकत की, जिसके बाद भारत ने कहर बरपा दिया था।



इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा

इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत ने कम समय में पाकिस्तानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे थे। उन्होंने कहा कि 36 घंटे के भीतर कम से कम 80 ड्रोन सीमा पार कर गए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने उनमें से 79 को रोक लिया, लेकिन एक ड्रोन सैन्य ठिकाने पर हमला करने में कामयाब रहा, जिससे लोग घायल

हुए। डार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने 9 मई की रात को स्थिति पर चर्चा करने और कुछ फैसलों को मंजूरी देने के लिए एक बैठक की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयर बेस पर हमला करके "गलती की।"

नूर खान एयरबेस पर हमला अहम क्यों

36 घंटे में 80 ड्रोन अटैक...

नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान का सबसे अहम सैन्य अड्डा है। यह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हवाई हमलों का शिकार हुआ था। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटजिक कमांड इसी नूरखान एयरबेस पर मौजूद है और उसकी कुछ परमाणु मिसाइलों समेत कई प्रमुख हथियारों को यहां तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नागरिक सरकार के वरिष्ठ नेता इसी एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान आने वाले वीवीआईपी गेस्ट भी नूर खान एयरबेस पर ही लैंड करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर किया था हमला

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान सहित पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेसों पर हमले किए थे। इनमें सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबाद और मुरीदके में एयरबेस शामिल थे। भारत के इन हवाई हमलों में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। इनके अलावा पाकिस्तानी रडार साइट, विमानों को रखने वाले हंगर और रनवे भी नष्ट हुए थे। पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमले और उनको पहुंचे नुकसान की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी।

Top News नेतन्याहू की मीडिया से जंग क्यों?

गाजा में इजरायल ने 300 पत्रकारों और उनके 700 से ज्यादा परिजनों की हत्या की, नेतन्याहू की मीडिया से जंग क्यों?

गाजा/तेल अवीव: अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा में जो अभियान चलाया, उसमें 70 हजार से ज्यादा लोग मारे गये हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा पत्रकारों की हत्या को लेकर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में 300 पत्रकार और उनके 700 से ज्यादा परिजन मारे गये हैं। यानि कहा जा सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं, पत्रकारों के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी थी। फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायल ने फिलिस्तीनी पत्रकारों के कम से कम 706 परिवार के सदस्यों को मार डाला है।

सिंडिकेट की फ्रीडम कमेटी ने शनिवार देर रात इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इजरायली सेना जानबूझकर पत्रकारों के परिवारों को निशाना बना रही है। ताकि फिलीस्तीन को लेकर रिपोर्टिंग ना हो

सके। इसका मकसद पत्रकारों की रिपोर्टिंग रोकना, उन्हें चुप करना, डराना और सच्चाई को बाहर आने से रोकना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमले युद्ध के कारण होने वाली मौतों के बजाय एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं।

इजरायल ने जान बूझकर पत्रकारों को निशाना बनाया? यूनियन ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ इजरायली हिंसा "और ज्यादा खतरनाक और क्रूर रूप ले चुकी है, जिसमें पत्रकारों के परिवारों और रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। यह पत्रकारिता के काम को एक ऐसा अस्तित्व का बोझ बनाने की साफ कोशिश है, जिसकी कीमत बेटे, पत्नियां, पिता और माताएं चुकाते हैं।" कमेटी के प्रमुख मुहम्मद अल-लह्दाम ने कहा कि 2023 से 2025 के बीच सामने आए मामलों से यह साफ होता है, कि इजरायल का मकसद गाजा में सच्चाई की आवाज को कुचलना है। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी जंग है जिसमें कैमरे और बच्चे के बीच,

कलम और घर के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा।" रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों के बेटे-बेटियां, पत्नियां, माता-पिता और बुजुर्ग रिश्तेदारों को मारा गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में 436, 2024 में 203 और 2025 में अब तक कम से कम 67 पत्रकारों के परिजनों की मौत हुई है। यह सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा, जब कई पत्रकारों के परिवार पहले ही अपने घरों से विस्थापित होकर टेंटों और अस्थायी शिविरों में शरण ले चुके थे। सिंडिकेट ने खान यूनिस के पास के एक मामले का उदाहरण दिया, जहां पत्रकार हिबा अल-अबादला, उनकी मां और अल-अस्ताल परिवार के करीब 15 सदस्यों के शव लगभग दो साल बाद मलबे से निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे कई मामलों में पूरे-के-पूरे परिवार खत्म कर दिए गये,, जबकि पत्रकार जीवित बच गए, ताकि वे अपने ही परिवार की तबाही के गवाह बनें।

पत्रकारों के खिलाफ इजरायल ने क्यों शुरू

की जंग? जांच रिपोर्ट के नतीजों में कहा गया है कि इजरायली हमलों ने बार-बार पत्रकारों के घरों, विस्थापन स्थलों और उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां मीडियाकर्मी और उनके रिश्तेदार रहते हैं। कुछ मामलों में पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि पत्रकारों को व्यक्तिगत निशाना बनाने के लिए उनके परिवार को खत्म किया गया है। इन मौतों की संख्या के अलावा, सिंडिकेट ने गंभीर मानसिक नुकसान की भी चेतावनी दी है। जिन पत्रकारों ने अपने बच्चों, पति या पत्नी, या माता-पिता को खोने के बाद भी जान बचाई है, वे अब ट्रॉमा में हैं, भारी अपराधबोध का सामना कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके परिवार की वजह से उनके परिवारवाले मारे गये हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 300 पत्रकारों की हत्या की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि 2025 में इजरायल ने किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा पत्रकारों की जान ली है।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Monday 29th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 243 , पृष्ठ 03

नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया:
आयुष छात्रों को बड़ी
राहत, अंतिम तिथि बढ़ी



अकोला (लोकसत्ता): महाराष्ट्र में आयुर्वेद, युनानी व होमिओपैथी (AYUSH) में पढ़ाई कर रहे कई छात्रों को नर्सिंग कोर्स प्रवेश में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि एएनएम, जीएनएम और बीएससी-नर्सिंग जैसे कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इससे वे नर्सिंग में दाखिला लेने से वंचित होने वाले थे।

स्थिति को देखते हुए 'प्रायव्हेट नर्सिंग स्कूल अँड कॉलेज मॅनेजमेंट असोशिएशन' ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी आगे बढ़कर समयसीमा बढ़ाने की मांग की।

केंद्र और इंडियन नर्सिंग कौन्सिल के हस्तक्षेप से अब प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे उन हजारों विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। यह राहत उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो AYUSH कोर्स में प्रवेश न मिलने पर नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते थे।

गिरोह ने बुजुर्ग से 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी, 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर फंसा दिया



संवाददाता |

सांगली मिरज में साइबर ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर एक वरिष्ठ नागरिक से 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी रविंद्र कुलकर्णी को क्राइसएप पर अज्ञात कॉलर ने फोन कर बताया कि उनके नाम पर विजय मल्ल्या गिरोह की 250 नकली बैंक पासबुक मिली हैं और मुंबई के कुलाबा पुलिस स्टेशन व CBI, RBI द्वारा उनके बैंक खातों की जांच जारी है।

ठगों ने कहा कि यदि कुलकर्णी 95% राशि जमा नहीं करेंगे, तो उन्हें तुरंत डिजिटल

मिरफ्तार किया जाएगा तथा उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। डर दिखाकर उन्हें RTGS के माध्यम से तीन बैंकों — स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC — के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

इस धोखाधड़ी के संदर्भ में मिरज शहर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आर्थिक फसवणुकी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में यह पाया जा रहा है कि ठगों ने डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे कानूनी दावों का इस्तेमाल कर बुजुर्गों को डराकर बड़ी रकम हड़पी।

RSS धार्मिक तनाव पैदा करने में सबसे आगे, संजय राउत ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर संघ पर बोला हमला

मुंबई/ठाणे: कांग्रेस पार्टी आज अपने 140वें स्थापना दिवस को मना रही है लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जहां दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है तो वहीं दूसरी उद्भव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि मैं उनसे पूछूंगा कि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को लेकर उनके दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आया? राउत ने शनिवार को कहा कि वह उनके मित्र हैं। दरअसल, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारी पार्टी का इतिहास 140 साल पुराना है। हम इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि संगठन मजबूत होना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। यह सोचने का विषय है। हमारे संगठन में अनुसान होना चाहिए। सिंह के इस बयान पर बवाल मच गया था।

दिग्विजय सिंह की X पोस्ट वायरल इस बयान पर अभी चर्चा चल रही थी कि दिग्विजय सिंह ने कि उन्होंने फिर से RSS-BJP की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे हैं।

कांग्रेस के ही कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट की आलोचना की है। इसके बाद कांग्रेस के अंदर घमासान शुरू हो गया था। दिग्विजय सिंह की यह पोस्ट वायरल हो चुकी है। इस पोस्ट ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला दिया है, हालांकि इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुद को आरएसएस और मोदी का विरोधी करार दिया है, लेकिन बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। यह मुद्दा महाराष्ट्र पहुंच गया है।

संघ पर फट पड़े संजय राउत अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के RSS की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा ने प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि RSS ने देश की आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। संघ ने 50 सालों तक अपने दफ्तरों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कभी नहीं फहराया या दिखाया। आरएसएस देश में धार्मिक तनाव पैदा करने में सबसे आगे है। मैंने देखा है कि दिग्विजय सिंह जी ने संसद में संघ पर बहुत जोरदार हमला किया था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? वह मेरे दोस्त हैं, और मैं उनसे समझूंगा कि उनकी राय में यह बदलाव कैसे आया।

BMC Election | ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से मुंबई में BJP की जरूरत बने एकनाथ शिंदे

BMC Election: ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से मुंबई में BJP की जरूरत बने एकनाथ शिंदे, 20 सीटों पर फैसला बाकी



ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने के बाद महायुति अलायंस मुंबई में टूट गया है। ऐसी ही स्थिति महाविकास आघाड़ी की हुई है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है।

बीजेपी अब दिख रही है नरम मुंबई बीएमसी चुनाव में नामांकन के लिए अब महज दो दिन और शेष बचे हैं। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

की शिवसेना के बीच चल रही मेराथन बैठकों के बाद भी करीब 20 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी ने मुंबई में पहली बार अपना महापौर बनाने के लिए बीजेपी में 150 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी प्रारंभ से चल रही थी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से एकनाथ शिंदे की अहमियत बढ़ गई। अब उनकी पार्टी की सीटों की संख्या 90 तक पहुंचती दिख रही है।

बीजेपी शिंदे की जिद के आगे झुकती दिख रही है। मुंबई में महापौर बनाने का सपना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वर्षों से देखता रहा है। सूत्रों की मानें तो 227 सीटों वाली मुंबई बीएमसी में 150+ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और कम से कम 130 उम्मीदवारों को जिताकर अपने दम पर पार्टी का महापौर बनाने की रणनीति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बनाई गई थी। शिंदे का दावा है कि बीएमसी के लगभग 80 पूर्व नगरसेवक उनके साथ हैं।

मुंबई चुनाव में महायुति का नया फार्मूला सामने आया है। शिंदे गुट की मांग पर अजित पवार की एनसीपी बाहर हो गई। बीजेपी-शिवसेना में 207 सीटों पर सहमति बनी है। ठाकरे भाइयों का संभावित गठबंधन बीजेपी की बड़ी चिंता बना हुआ है।



बारामती में AI सेंटर का उद्घाटन: गौतम अडानी ने शरद पवार को बताया 'मेरे मार्गदर्शक'

बारामती (पुणे): उद्योगपति गौतम अडानी ने रविवार को महाराष्ट्र के बारामती में “शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार की जोरदार प्रशंसा की और उन्हें अपना “मार्गदर्शक (मेंटर)” बताया। यह कार्यक्रम राजनीतिक और सार्वजनिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान देने योग्य रहा।

उद्घाटन समारोह में शरद पवार, संसद सदस्य सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। यह सेंटर विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसे पवार परिवार द्वारा संचालित शैक्षणिक

संस्थान कहा गया है। अपने संबोधन में गौतम अडानी ने कहा कि वह शरद पवार को तीन दशकों से जानते हैं और उनसे जो कुछ भी सीखा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। उन्होंने पवार की राजनीति, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना मेंटर बताया। अडानी ने बारामती को “एक ऐसा स्थान” कहा जो विकास, परिवर्तन और अवसरों का प्रतीक बन चुका है, और इसे पवार की दूरदर्शिता से जोड़ा। अडानी ने यह भी कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि नेता और निर्माता बनना चाहिए, और इस दिशा में यह केंद्र युवाओं तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन देगा। उन्होंने तकनीक और प्रतिभा के साथ राष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

बीएमसी चुनाव 2026: अजित पवार की NCP ने पहली उम्मीदवार सूची जारी की



मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 से पहले **हिंदी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी नेता अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस घोषणा से मुंबई के चुनावी रण में नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है।

पार्टी की विधायक सना मलिक ने 28 दिसंबर 2025 को मीडिया के सामने यह सूची पेश की जिसमें कुल 37 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और इस प्रारंभिक सूची में NCP ने कई मौजूदा कॉर्पोरेटर्स को प्राथमिकता देते हुए युवा और पहली बार चुनाव लड़ने वालों को भी मौका दिया है।

सूची की घोषणा करते हुए सना मलिक ने कहा कि पार्टी ने अपने मौजूदा कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को तरजूह दी है और इससे नए चेहरों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। खास बात यह रही कि कई युवा तथा युवा महिलाएं पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं, जो पार्टी की नीतियों में बदलाव और युवा सशक्तिकरण को

दर्शाता है।

इस चुनाव में NCP महायुति (शिवसेना-भाजपा गठबंधन) से अलग अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अपने दम पर मुंबई नगर निगम में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पहले यह भी रिपोर्ट है कि NCP लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी की सूचियाँ बाद में जारी होंगी।

सूची में शामिल नामों में विभिन्न वर्गों से उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व है, जैसे कि:

वार्ड 3: मनीष दुबे, वार्ड 48: सिरिल पीटर डिस्सुजा, वार्ड 62: अहमद खान, वार्ड 96: आयशा शम्स खान, वार्ड 148: सोमू चंदू पवार, वार्ड 165: अब्दुल रशीद (कप्तान) मलिक, वार्ड 168: डॉ. सईदा खान, वार्ड 170: बृशरा परवीन मलिक, वार्ड 197: फरीन इम्टियाज खान आदि शामिल हैं।

बीएमसी चुनावों के अंतर्गत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2025 है, जबकि मतदान 15 जनवरी 2026 को होना निर्धारित है और मतगणना उसके अगले दिन होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस प्रारंभिक उम्मीदवार सूची से एनसीपी की चुनावी रणनीति और स्थानीय समीकरणों पर ध्यान देने का प्रयास स्पष्ट दिखता है। पार्टी ने सामाजिक, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधता का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों के चयन पर जोर दिया है, ताकि मुंबई के मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके।

कांग्रेस ने मुंबई में खोज लिया नया साथी, प्रकाश अंबेडकर की VBA के साथ आगे बढ़ेगी चुनावी गाड़ी! ऐलान जल्द

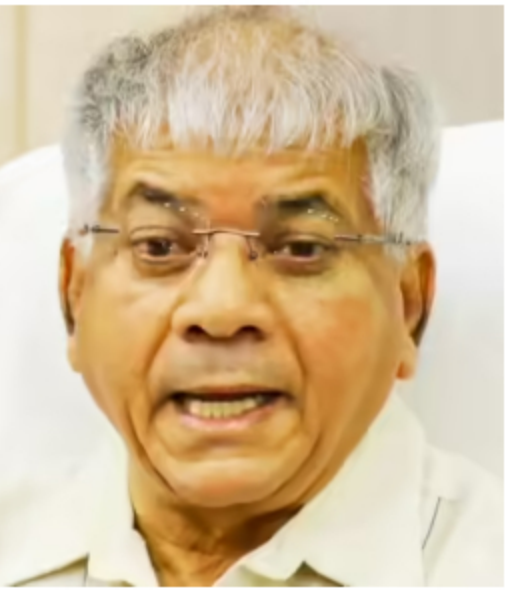
● NEWS AGENCY

मुंबई: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन में अब सिर्फ दो बाकी रह गए हैं। 29 और 30 दिसंबर को ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इस सब के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें कहा जा रहा है कि मुंबई में मनसे के कारण उद्भव ठाकरे से दूर हुई कांग्रेस चुनावी मैदान में प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) को साथ ले सकती है। कांग्रेस और वीबीए का अलायंस हो सकता है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और वीबीए का गठबंधन बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी होगा। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर को साथ नहीं ले पाई थी। महानगरपालिका चुनावों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे।



पहली बार कांग्रेस-VBA गठबंधन!

2024 के लोकसभा और असेंबली चुनावों के दौरान अलायंस की बातचीत फेल होने के बाद, यह पहली बार होगा जब कांग्रेस वीबीए के साथ हाथ मिलाएगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस-VBA अलायंस का अनाउंसमेंट आज हो सकता है। बीएमसी चुनावों के साथ-साथ 28 दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराष्ट्र की अलायंस



पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें महा विकास अघाड़ी (MVA) की पार्टियां अलग-अलग रास्ते अपना रही हैं। ठाकरे भाई, जो सालों से अलग-थलग थे, 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनावों से पहले अलायंस करने के लिए एक साथ आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ महायुति से अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) बाहर हो गई है। वह अकेले लड़ रही है।

बीजेपी-शिवसेना की डील इन मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच बात बन गई है। 227 में 207 सीटों पर तय हो चुका है कि कौन पार्टी का कैंडिडेट किस सीट से लड़ेगा। मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट अमित साठम ने शनिवार को कहा कि महायुति 207 सीटों पर सीट-शेयरिंग पर सहमत हो गई है, जिसमें BJP 128 सीटों पर और शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साठम ने कहा कि बाकी 20 सीटों पर फैसला कैंडिडेट के आधार पर होगा। महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य भर में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की घोषणा की है, जिसमें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) और पिंपरी-चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) शामिल हैं। वोटिंग 15 जनवरी को होगी। काउंटिंग 16 जनवरी को होगी।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



नंदिग्राम टाइम्स

Monday 29th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 243 , पृष्ठ 04

नांदेड़: अवैध गोवंश तस्करी में 10 गोवंश व वाहन-मुद्देमाल ₹17.30 लाख जप्त

नांदेड़ : नांदेड़ ग्रामीण पुलिस ने अवैध गोवंश तस्करी के एक बड़े मामले में शुक्रवार रात महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए दस गोवंश, एक ट्रक और अन्य सामान सहित कुल लगभग ₹17.30 लाख का मुद्देमाल जप्त किया है। यह कार्रवाई ओपरेशन फ्लैश आउट के तहत की गई, जिसे जिल्हा पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने राज्य भर में लागू किया है।

पुलिस टीम ने विष्णुपुरी कॅनल के पास गश्त के दौरान MH-26 BE 4946 नंबर के ट्रक को रोका, जिसमें गोवंश को निर्दयी तरीके से खूबकर और बांधकर ले जाया जा रहा था। निरीक्षण में ट्रक से दस गोवंश और वाहन-सामान मिला, जिसकी कीमत लगभग ₹17.30 लाख आंकी गई है।

इस घटना के संबंध में जबीउल्लाखान जहीरउल्लाखान, मोहंमद गौस, शेख कलीम और शेख उमर कुईशी सहित चार नामज़द आरोपियों के खिलाफ ग्रामीण पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई है। अवैध गोवंश तस्करी रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में अन्य संभावित गिरोहों को भी बैकफुट पर लाने का प्रयास मानी जा रही है।

नांदेड़ महापालिका चुनाव नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल, उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर मंथन तेज

नांदेड़ | आगामी 15 जनवरी को होने वाले नांदेड़-वाघाला शहर महानगरपालिका के आम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 20 प्रभागों से 81 नगरसेवकों के चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यह चुनाव जिले के तीन सांसदों और चार विधायकों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री सांसद अशोकराव चव्हाण और सांसद डॉ. अजित गोपछड़े चुनावी रणनीति की कमान संभाले हुए हैं। पार्टी का लक्ष्य महापालिका में बहुमत हासिल करना है, जिसके लिए जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने पर जोर दिया जा रहा है।



पुराने और नए कार्यकर्ताओं के संतुलन के साथ उम्मीदवार चयन को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं शिवसेना के विधायक बालाजीराव कल्याणकर, आनंद बोंडारकर और विधान परिषद सदस्य हेमंत पाटील भी अपने-अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं।

बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना में मतभेद उभरकर सामने आए हैं। उत्तर और दक्षिण नांदेड़ में शिवसेना की रणनीति अलग-अलग दिखाई दे रही है, जिससे गठबंधन की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक प्रतापराव पाटील

चिखलीकर ने भी किसी भी तरह की संभावित युति को ध्यान में रखे बिना तैयारी शुरू कर दी है। दलित और मुस्लिम बहुल प्रभागों में अधिक उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

कांग्रेस की ओर से सांसद प्रो. रविंद्र चव्हाण ने सभी प्रभागों में उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। नवा मोढा स्थित पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों के माध्यम से संगठन को सक्रिय किया जा रहा है।

कुल मिलाकर नांदेड़ महानगरपालिका का यह चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता का नहीं, बल्कि जिले के प्रमुख नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहा है।



चंद्रपूर किडनी रैकेट: किसान की किडनी 12 घंटे में ट्रांसप्लांट, SIA ने खोली खलनायक कड़ी

चंद्रपूर: विशेष जांच टीम (SIT) ने महाराष्ट्र के चंद्रपूर किडनी रैकेट मामले में चौकाने वाला खुलासा किया है कि किसान रोशन कुले की **किडनी निकाले जाने के महज 12 घंटे के भीतर इसे कंबोडिया में चीनी मरीज को प्रत्यारोपित किया गया। यह जानकारी दो मुख्य आरोपियों के बयान से मिली है, जिनमें सोलापुर का रामकृष्ण सुंचू (उर्फ 'डॉ. कृष्णा'/मल्लेश) और चंदीगढ़ का हिमांशु भारद्वाज शामिल हैं। थाना नागभीड़ के मिथूर गांव निवासी कुले को कर्ज के

दबाव में यह कदम उठाना पड़ा, जिससे यह संगठित अवैध नेटवर्क उजागर हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि चाइनीज़ सर्जन डॉ. चियांग कंबोडिया में प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं का संचालन करते थे और प्राप्त किडनियों को चीन के रोगियों को उपलब्ध कराते थे। एसआईटी अब इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट के वित्तीय और तस्करी झांकियों की जांच कर रही है, जबकि एक तीसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार है।

ZP NANDED | जिला परिषद की जर्जर स्कूल इमारतों को अवमूल्यन

जिला परिषद की जर्जर स्कूल इमारतों को अवमूल्यन (निर्लेखन) करने के निर्देश

नांदेड़ | जिला परिषद के अधीन संचालित जर्जर एवं खतरे की स्थिति में पहुंच चुकी स्कूल इमारतों व कक्षाओं को अवमूल्यन (निर्लेखन) करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में संबंधित विभागों को विस्तृत मार्गदर्शक प्रक्रिया का पालन करने के आदेश दिए गए हैं।



निर्देशों के अनुसार, जिला परिषद के अंतर्गत जिन स्कूल इमारतों अथवा कक्षा कक्षों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, उनका प्रस्ताव संबंधित पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत बीडीओ एवं उप-अभियंता (निर्माण) द्वारा संयुक्त रूप से भवन की संरचनात्मक जांच (स्ट्रक्चरल ऑडिट) कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) को प्रस्तुत की जाएगी।

सके पश्चात शिक्षणाधिकारी द्वारा कार्यकारी अभियंता की राय प्राप्त कर उक्त प्रस्ताव को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव में संबंधित भवन के निर्माण वर्ष, भवन स्थित भूमि का स्वामित्व

विवरण, किस योजना के अंतर्गत निर्माण हुआ, कुल क्षेत्रफल, निर्माण लागत, वर्तमान स्थिति का विवरण, जर्जर भवन का घसारा मूल्य, मूल्यांकन तथा भवन ध्वस्त करने की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रहेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद तथा जिला परिषद की सर्वसाधारण समिति एवं जिला परिषद अध्यक्ष की अंतिम मंजूरी प्राप्त होने पर संबंधित भवन में दर्ज करने की जिम्मेदारी उप-अभियंता (निर्माण) पर रहेगी।

इसके अतिरिक्त, उप-अभियंता द्वारा ही नीलामी (लिलाव) पद्धति के माध्यम से जर्जर इमारत को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस निर्णय से विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ भविष्य में नए भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नांदेड़ मनपा की,

लापरवाही से सिडको क्षेत्र की सड़कें और नालियां बदहाल

मनपा की लापरवाही से सिडको क्षेत्र की सड़कें और नालियां

बदहाल पूर्व नगरसेवकों ने गंभीर समस्याओं से साधी दूरी

● नांदेड़ (संवाददाता): नांदेड़ महानगरपालिका के सबसे बड़े प्रभाग सिडको-हडको को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सड़क के साथ-साथ क्षेत्र की नालियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूर्व में निर्वाचित नगरसेवकों की अनदेखी और मनपा प्रशासन की उदासीनता के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को इस मार्ग से गुजरते समय जान जोखिम में डालनी पड़ रही है।

सिडको से श्मशानभूमि मार्ग होते हुए हडको जाने वाला यह रास्ता क्षेत्र का प्रमुख और निकटतम मार्ग है। इसी कारण इस सड़क

पर प्रतिदिन भारी यातायात रहता है। सिडको कार्यालय के अस्तित्व के दौरान इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में महानगरपालिका की लचर कार्यप्रणाली के चलते यह मार्ग वर्षों से खस्ताहाल पड़ा हुआ है।

विशेष रूप से दलित वस्ती सुधार योजना के अंतर्गत गोविंद कॉलोनी क्षेत्र में सड़क निर्माण के बाद बार-बार खुदाई किए जाने से सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो गई। मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है।

क्षेत्र से सिडको-हडको के पांच नगरसेवक चुने जाते हैं, लेकिन

वर्ष 2017 के नगर निगम चुनाव में दिए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। नतीजतन सड़कें और नालियां पूरी तरह जर्जर हो गई हैं। अब आगामी चुनावों को देखते हुए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा एक बार फिर आश्वासनों की झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन नागरिकों में इन वादों को लेकर भारी संदेह बना हुआ है।

स्थानीय नागरिकों की मांग है कि चुनावी घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रशासन और जनप्रतिनिधि स्थायी समाधान पर ध्यान दें, ताकि सिडको क्षेत्र को इस बदहाली से मुक्ति मिल सके।

● ● ● ● ● ● ● ●

नांदेड़: नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शरद पवार ने जताया चिखलीकर परिवार के प्रति आजीवन समर्थन



नांदेड़ : लोहा नगरपरिषद के नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शरद नामदेवराव पवार ने शनिवार को चिखलीकर परिवार के प्रति अपनी दीर्घकालिक निष्ठा का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब वह आयुष्य भर आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर एवं उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। यह बयान उन्होंने वसंतनगर स्थित चिखलीकर परिवार के सत्कार समारोह में दिया।

कार्यक्रम में प्रतिभाताई पाटील चिखलीकर, प्रदेश सरचिटणीस प्रविण पाटील चिखलीकर, सचिन पाटील चिखलीकर सहित क्षेत्रीय NCP

कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद थे। शरद पवार ने कहा कि नगराध्यक्ष बनने का पूरा श्रेय चिखलीकर परिवार को जाता है, इसलिए वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।

समारोह में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने पवार की भावनात्मक प्रतिबद्धता का स्वागत किया। राजनीति में पारिवारिक व संगठनात्मक समर्थन के महत्व को उजागर करते हुए नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष ने स्थानीय नेताओं और जनता के बीच एकता का संदेश भी दिया।

इस विकास से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में परिवार-आधारित समर्थन और गठबंधन की भूमिका आज भी निर्णायक बनी हुई है। आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए इस तरह के समर्थन को राजनीतिक मजबूती का संकेत भी माना जा रहा है।

नांदेड़ मनपा चुनाव: एमआईएम ने 5 प्रभागों से 20 उम्मीदवार उतारकर बढ़ाई सियासी सरगर्मी

●

नांदेड़: आगामी महानगरपालिका चुनाव की रणधुमाल में नांदेड़ का राजनीतिक वातावरण इन दिनों खासा गर्म हो गया है। जहां शहर के प्रमुख राजनीतिक दल अभी भी गठबंधन, आघाड़ी और सीटों के बंटवारे के जटिल समीकरणों में उलझे नजर आ रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) ने समय से पहले अपने पते खोलते हुए चुनावी मैदान में बढ़त बना ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देशानुसार एमआईएम ने नांदेड़ महानगरपालिका के 5 महत्वपूर्ण प्रभागों से 20 उम्मीदवारों की घोषणा कर सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है।

एमआईएम द्वारा की गई यह घोषणा ऐसे समय पर सामने आई है, जब अन्य दलों में उम्मीदवारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस बार चुनाव को गंभीर रणनीति और संगठित तैयारी के साथ लड़ने के मूड में है।



कठोर मुलाखत प्रक्रिया से गुजरना पड़ा नेताओं को

कांग्रेस से एमआईएम में शामिल हुए मसूद खान, शमीम अब्दुल्ला, चांद पाशा और लतीफ पठाण जैसे अनुभवी नेताओं का नाम इस सूची में शामिल है। इन नेताओं ने पूर्व में कई बार महापालिका चुनाव जीतकर अपने-अपने प्रभागों में मजबूत पकड़ बनाई है। इसके बावजूद एमआईएम ने टिकट देते समय केवल उनके पुराने राजनीतिक अनुभव पर भरोसा नहीं किया। पार्टी ने सभी संभावित उम्मीदवारों को



कठोर साक्षात्कार और आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मैदान में उतारा है।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों की वर्तमान जनसंपर्क क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव और संगठनात्मक सक्रियता की गहन पड़ताल की गई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि केवल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि मौजूदा जनसमर्थन के आधार पर ही चुनावी टिकट दिया जाना चाहिए। रणनीतिक बढ़त, परिणाम पर टिकी नजर

प्रमुख दलों में अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा और गठबंधन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में एमआईएम द्वारा समय रहते 20 उम्मीदवारों की घोषणा को राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य दल इस चुनौती का किस प्रकार जवाब देते हैं और एमआईएम की यह रणनीति मतदान के दिन कितनी प्रभावी साबित होती है।

एमआईएम के घोषित 20 उम्मीदवार

प्रभाग 05: प्रजा सूर्यवंशी, शिफा मुस्कान शेख, हाजरा बेगम, मुफ्ती अशर अली खान
प्रभाग 11: मोहम्मद मसूद अहमद खान, आसिया बेगम बागवान, सैयद फसिउद्दीन, सायमा खान
प्रभाग 12: अब्दुल रशीद, बेबी शाइस्ता, कमर सुलताना बी, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन
प्रभाग 13: अब्दुल लतीफ, अश्विनी धोंगडे, सैयद मुजीब, मरियम सानिया
प्रभाग 14: रेहाना बेगम, शमीम बेगम बागवान, शमी अब्दुल्ला, स्वाती हसेकर